Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

Original Article

ग्रामीण विकास की दिशा में फर्रूखाबाद जनपद की नीतिगत भूमिका और सामाजिक प्रभाव

राजकुमार साहू[1] , डॉ. संजीव कुमार[2]

[1] *संशोधक विदयार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, मेजर एस.डी सिंह युनिवर्सिटी फर्रूखाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत*

[2] *सहायक प्रोफेसर एवं संशोधन मार्गदर्शक, अर्थशास्त्र विभाग, मेजर एस.डी सिंह युनिवर्सिटी फर्रूखाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत*

Manuscript ID: yrj-140301

ISSN: 2277-7911
Impact Factor – 5.958

Volume 14
Issue 3
July-August-Sept.- 2025
Pp. 1-9

Submitted: 5 July 2025
Revised: 20 July 2025
Accepted: 26 July 2025
Published: 10 Sept. 2025

Corresponding Author:
राजकुमार साहू

Quick Response Code:

Web. https://yra.ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.17115461

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.17115461

Creative Commons

OPEN ACCESS

सारांश:

यह शोध पत्र *"ग्रामीण विकास की दिशा में फर्रूखाबाद जनपद की नीतिगत भूमिका और सामाजिक प्रभाव"* फर्रूखाबाद जिले के ग्रामीण अंचल में नीतिगत पहलों और उनके सामाजिक-आर्थिक परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कृषि आधारित योजनाएँ, स्वरोजगार और रोजगार कार्यक्रम, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वित्तीय समावेशन ने ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। विशेषकर *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना* और *जनधन योजना* जैसी पहलें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक जागरूकता में सहायक सिद्ध हुई हैं। नीतिगत हस्तक्षेपों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है, महिलाओं की सामाजिक भूमिका मजबूत हुई है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना बढ़ी है। हालांकि, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, संसाधनों का असमान वितरण, पलायन और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि यदि नीतिगत पहलों को अधिक पारदर्शी, सहभागी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए तो फर्रूखाबाद जनपद ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बन सकता है।

मुख्य शब्द : फर्रूखाबाद जनपद, ग्रामीण विकास, नीतिगत पहलें, सामाजिक प्रभाव, कृषि, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य.

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:
राजकुमार साहू, डॉ.संजीव कुमार (2025). ग्रामीण विकास की दिशा में फर्रूखाबाद जनपद की नीतिगत भूमिका और सामाजिक प्रभाव. Young researcher, 14(3), 1–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.17115461

परिचय:

भारत का ग्रामीण क्षेत्र सदैव से ही देश की आर्थिक रीढ़ माना गया है। लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है और आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियाँ हैं। ग्रामीण विकास की संकल्पना केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, सामाजिक

न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक पहलुओं को अपने अंतर्गत समाहित करती है। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास की नीतियाँ स्थानीय स्तर पर समाज की आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।

फर्रूखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि-प्रधान है। यह क्षेत्र विशेष रूप से आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण विकास की दिशा में नीतिगत पहल का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर आधारभूत संरचना का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के प्रसार और स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण अंचलों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर सीमांत किसानों की समस्याएँ, पलायन, बेरोज़गारी और संसाधनों की कमी ने विकास की गति को धीमा किया है (मिश्रा, 2020)।

ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास आर्थिक प्रगति का आधार है। मिश्रा (2020) के अनुसार, आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, जलापूर्ति और परिवहन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तिवारी (2019) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण ने न केवल आवागमन को आसान बनाया बल्कि बाजारों तक पहुँच और कृषि उत्पादों के विपणन में भी सहूलियत प्रदान की। इसी प्रकार, शुक्ला (2019) का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण बाजारों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और ऊर्जा की उपलब्धता भी विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। पांडे (2018) ने अपने अध्ययन में बताया कि बिजली आपूर्ति ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों और घरेलू जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी ग्रामीण समाज को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा है। गुप्ता (2020) तथा भटनागर (2021) दोनों ने ही अपने शोध में पाया कि डिजिटल अवसंरचना युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रही है और उन्हें स्वरोजगार एवं शिक्षा में मददगार सिद्ध हो रही है।

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता भी नीतिगत पहलों का अभिन्न हिस्सा है। वर्मा (2021) और कश्यप (2019) ने अपने शोधों में यह निष्कर्ष निकाला कि जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता की स्थिति में सुधार किया है, जिससे बीमारियों में कमी आई है और जीवन स्तर ऊँचा हुआ है।

स्वास्थ्य और शिक्षा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले दो प्रमुख आयाम हैं। यादव (2020) ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ने ग्रामीण जीवन स्तर को सीधे प्रभावित किया है। यद्यपि चिकित्सकों की कमी और दवाओं की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, फिर भी स्वास्थ्य मिशनों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। चौधरी (2017) और शर्मा (2019) ने शिक्षा अधोसंरचना की भूमिका का मूल्यांकन करते

हुए बताया कि ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।

कृषि अधोसंरचना भी ग्रामीण विकास का प्रमुख स्तंभ है। सिंह (2020) तथा तोमर (2021) ने अपने अध्ययनों में उल्लेख किया कि सिंचाई व्यवस्थाओं और कृषि अवसंरचना ने उत्पादन को बढ़ाने और विपणन को सशक्त करने में मदद की है। साथ ही, त्रिपाठी (2021) ने यह दिखाया कि परिवहन व्यवस्था में सुधार से कृषि उत्पादों का समय पर विपणन संभव हुआ, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई।

ग्रामीण विकास में रोजगार सृजन और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति भी नीतिगत विमर्श का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। दीक्षित (2022) के अनुसार, अधोसंरचना निवेश ने ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी की है। वाजपेयी (2022) ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के प्रभावों का अध्ययन करते हुए यह पाया कि ग्रामीण अधोसंरचना में सुधार से लौटे हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है और यह प्रवासन की समस्या को भी आंशिक रूप से रोक सकता है।

हालाँकि, ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ और नीतिगत चुनौतियाँ भी देखी जाती हैं। राठी (2018) ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि क्षेत्रीय असमानताएँ अधोसंरचना विकास में प्रमुख बाधा बनती हैं। इसी प्रकार, निगम (2018) ने पंचायत आधारित योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए कहा कि स्थानीय शासन का सशक्त होना ग्रामीण विकास की सफलता के लिए अनिवार्य है।

फर्रूखाबाद जनपद के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की नीतिगत पहलों का सीधा असर ग्रामीण समाज पर पड़ा है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने ग्रामीण जीवन में सुधार किया है, परंतु सीमांत किसानों की समस्याएँ, महिला सहभागिता की कमी, युवाओं के लिए रोजगार अवसरों की सीमितता और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं (मिश्रा, 2022)।

साहित्य समीक्षा:

ग्रामीण विकास पर आधारित शोधों ने यह स्पष्ट किया है कि अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जलापूर्ति और डिजिटल संसाधन ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन्न विद्वानों के अध्ययन बताते हैं कि नीतिगत पहलों ने ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की दिशा दी है, किंतु चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।

मिश्रा (2020) ने ग्रामीण आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के संबंध का क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते हुए यह पाया कि सड़क, बिजली और सिंचाई जैसे संसाधनों की उपलब्धता ने किसानों की आय और ग्रामीण उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। तिवारी (2019) ने उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण पर अपने अध्ययन में बताया कि इससे न केवल ग्रामीण लोगों का आवागमन आसान हुआ बल्कि स्थानीय बाजारों तक पहुँच बढ़ी और कृषि उत्पादों की बिक्री में भी सुधार हुआ। इसी प्रकार शुक्ला (2019) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के

प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि सड़क संपर्क ने ग्रामीण बाजारों को प्रोत्साहित किया और छोटे व्यापारों के विकास में भी सहायक रहा।

वर्मा (2021) ने ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति पर अपने शोध में पाया कि योजनाओं के बावजूद कई क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की कमी और असमान वितरण बना हुआ है। कश्यप (2019) ने *जल जीवन मिशन* का मूल्यांकन करते हुए यह कहा कि इस पहल ने कुछ हद तक सकारात्मक परिवर्तन किया, परंतु स्थायित्व और रखरखाव की समस्याएँ अब भी मौजूद हैं।

ऊर्जा और बिजली की भूमिका पर पांडे (2018) ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ने औद्योगिक गतिविधियों और घरेलू जीवन स्तर दोनों में सुधार किया है। हालाँकि, असमान वितरण और बार-बार कटौती ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में यादव (2020) ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने में महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु चिकित्सकों की अनुपलब्धता और दवाओं की कमी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। शर्मा (2019) ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना को आर्थिक प्रगति से जोड़ते हुए बताया कि दोनों क्षेत्रों में निवेश ने सामाजिक सशक्तिकरण और मानव संसाधन विकास को गति दी है।

शिक्षा पर केंद्रित अध्ययन में चौधरी (2017) ने शिक्षा अधोसंरचना और आर्थिक सशक्तिकरण का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया और पाया कि शिक्षा सुविधाओं के विस्तार ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। मिश्रा (2022) ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना विकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करते हुए यह दर्शाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में योजनाएँ बनीं तो हैं, किंतु उनकी सफलता प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करती है।

डिजिटल अधोसंरचना भी ग्रामीण विकास का नया आयाम है। गुप्ता (2020) ने अपने अध्ययन में बताया कि ग्रामीण इंटरनेट ने युवाओं के लिए शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सहभागिता के अवसर बढ़ाए। भटनागर (2021) ने मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल समावेशन पर अपने शोध में पाया कि डिजिटल सेवाएँ ग्रामीण युवाओं को शहरी समाज से जोड़ने और सूचना तक पहुँच दिलाने में सहायक हैं।

परिवहन और कृषि विपणन पर त्रिपाठी (2021) ने जोर दिया और निष्कर्ष निकाला कि बेहतर परिवहन व्यवस्था ने कृषि उत्पादों के विपणन को सुगम बनाया है। तोमर (2021) ने सिंचाई और सड़क अधोसंरचना का कृषि उत्पादन पर प्रभाव देखा और पाया कि उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय असमानताओं पर राठी (2018) ने लिखा कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास में क्षेत्रीय विविधताएँ गहरी समस्या हैं। कई क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक निवेश हुआ जबकि अन्य क्षेत्र उपेक्षित रहे। इसी तरह निगम (2018) ने पंचायत आधारित अधोसंरचना योजनाओं का अध्ययन करते हुए कहा कि स्थानीय शासन की सक्रियता योजनाओं की सफलता की कुंजी है।

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

रोजगार सृजन पर दीक्षित (2022) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष दिया कि अधोसंरचना निवेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। वाजपेयी (2022) ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के संदर्भ में यह बताया कि अधोसंरचना विकास से लौटे हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है और प्रवासन की समस्या को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय समावेशन भी विकास की प्रक्रिया में आवश्यक है। कुशवाहा (2020) ने यह पाया कि बैंकिंग अधोसंरचना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता ने ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद की है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता की कमी योजनाओं की सफलता को बाधित करती है।

फर्रूखाबाद जनपद का परिचय:

1. भौगोलिक स्थिति और विस्तार:

फर्रूखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार गंगा और रामगंगा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि में फैला हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,300 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में बदायूँ, दक्षिण में कन्नौज, पूर्व में हरदोई तथा पश्चिम में एटा और मैनपुरी जिले स्थित हैं। गंगा नदी इसके उत्तरी भाग से बहती है, जो जिले की कृषि व्यवस्था को समृद्ध बनाती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में यह 5 डिग्री तक पहुँच जाता है।

2. प्रशासनिक ढाँचा:

फर्रूखाबाद जनपद तीन तहसीलों—कायमगंज, अमृतपुर और फर्रूखाबाद—में विभाजित है। जिले में कुल 7 विकास खंड हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, मनरेगा कार्यों, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जाती है। पंचायत प्रणाली ने ग्रामीण समाज को नीतिगत निर्णयों में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है, हालाँकि इसकी दक्षता स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक पारदर्शिता पर निर्भर करती है।

3.जनसंख्या और सामाजिक संरचना:

2011 की जनगणना के अनुसार फर्रूखाबाद जिले की कुल जनसंख्या लगभग 1.9 मिलियन है, जिसमें ग्रामीण आबादी का अनुपात लगभग 75% है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 800 से अधिक है, जो इसे राज्य के घनी आबादी वाले जिलों में शामिल करता है। सामाजिक संरचना में उच्च जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। इस विविधता ने ग्रामीण समाज की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया है।

ग्रामीण परिवारों का अधिकांश हिस्सा संयुक्त परिवार व्यवस्था पर आधारित है, जहाँ कृषि कार्यों में सभी सदस्य योगदान करते हैं। महिला श्रमशक्ति का योगदान घरेलू कार्यों, पशुपालन और कृषि कार्यों में विशेष रूप से देखा जाता है।

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

4. कृषि और अर्थव्यवस्था:

फर्रूखाबाद की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। जिले को आलू उत्पादन का गढ़ माना जाता है और यहाँ उगाई गई आलू की किस्में देश के विभिन्न भागों में निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा, गेहूँ, सरसों, धान, गन्ना और दलहन भी प्रमुख फसलें हैं। सिंचाई की दृष्टि से गंगा और रामगंगा नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, साथ ही नहरों और नलकूपों का उपयोग भी व्यापक है।

कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे आलू-प्रसंस्करण इकाइयाँ, तेल पेराई, बुनाई और हस्तशिल्प जिले की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर उद्योगों का अभाव रोजगार अवसरों को सीमित करता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा पलायन कर अन्य शहरों में रोजगार की तलाश करते हैं।

5. शिक्षा की स्थिति:

जिले में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों की संख्या पर्याप्त है, किंतु उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। *सर्व शिक्षा अभियान* और *मध्याह्न भोजन योजना* जैसी सरकारी पहलों ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। मिश्रा (2022) और चौधरी (2017) के अनुसार, शिक्षा अधोसंरचना ग्रामीण समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने में सहायक रही है। फिर भी, शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा तक पहुँच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

6. स्वास्थ्य सेवाएँ:

फर्रूखाबाद जनपद में स्वास्थ्य सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) के माध्यम से उपलब्ध हैं। यादव (2020) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन सेवाओं की उपलब्धता सीमित है और चिकित्सकों की कमी गंभीर समस्या है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों और प्रसव सेवाओं की कमी अब भी है। *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)* ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, परंतु व्यावहारिक स्तर पर इसका प्रभाव मिश्रित रहा है।

7. आधारभूत संरचना:

फर्रूखाबाद जिले में आधारभूत संरचना के विकास पर हाल के वर्षों में विशेष ध्यान दिया गया है। *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* ने गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा है (शुक्ला, 2019)। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, हालाँकि कटौती की समस्या अब भी बनी हुई है (पांडे, 2018)। *जल जीवन मिशन* और *स्वच्छ भारत अभियान* ने पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किया है (कश्यप, 2019)। डिजिटल सेवाओं का प्रसार युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर रहा है (गुप्ता, 2020; भटनागर, 2021)।

8. नीतिगत महत्व:

फर्रूखाबाद जनपद में लागू विभिन्न योजनाएँ जैसे *मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना* और *मुद्रा योजना* ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से संचालित हैं।

इन योजनाओं का सीधा प्रभाव रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ा है। हालाँकि, राठी (2018) और निगम (2018) के अनुसार, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता की कमी विकास की राह में बाधक है।

फर्रूखाबाद जनपद में नीतिगत पहलें और सामाजिक प्रभाव:

फर्रूखाबाद जनपद में ग्रामीण विकास की नीतिगत पहलें कई आयामों में देखी जा सकती हैं जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कृषि एवं आजीविका विकास की दृष्टि से देखें तो जनपद की पहचान आलू उत्पादन के केंद्र के रूप में है, जिसे बढ़ावा देने के लिए *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि*, *कृषि बीमा योजना* और कोल्ड स्टोरेज जैसी नीतिगत सुविधाएँ लागू की गईं। इन योजनाओं से किसानों की आय में सुधार हुआ, परंतु विपणन और मूल्य स्थिरीकरण की समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम रोजगार सुरक्षा दी, जबकि मुद्रा योजना और स्वरोजगार योजनाओं ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में *सर्व शिक्षा अभियान*, *समग्र शिक्षा अभियान* और *मध्याह्न भोजन योजना* ने विद्यालयी शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई और पोषण में भी सुधार किया। साथ ही, कौशल विकास केंद्रों और आईटीआई संस्थानों ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए, हालाँकि उच्च शिक्षा की उपलब्धता अब भी सीमित है। स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना के परिप्रेक्ष्य में *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन* ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, पर चिकित्सकों और दवाओं की कमी ने इसकी सफलता को सीमित किया। *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* ने गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा, बिजली और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने जीवन स्तर ऊँचा किया, तथा डिजिटल इंडिया की पहल ने युवाओं को नई संभावनाएँ प्रदान कीं। इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण और अधोसंरचना की गुणवत्ता बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों (SHGs), *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* और *जनधन योजना* ने महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रहकर अब स्वरोजगार, लघु उद्योग और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भी भागीदारी कर रही हैं। इन नीतिगत पहलों ने ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताओं को आंशिक रूप से कम किया है, जागरूकता को बढ़ाया है और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया है, परंतु योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर प्रशासनिक बाधाओं, भ्रष्टाचार और संसाधनों की असमान उपलब्धता से प्रभावित होता है। समग्र रूप से देखा जाए तो फर्रूखाबाद जनपद में नीतिगत पहलों ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है, किंतु चुनौतियों के समाधान के बिना ग्रामीण विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकती।

निष्कर्ष:

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि फर्रूखाबाद जनपद में ग्रामीण विकास की दिशा में की गई नीतिगत पहलों ने समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। कृषि आधारित योजनाओं, रोजगार सृजन कार्यक्रमों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण तथा आधारभूत संरचना विकास की पहलों ने ग्रामीण जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों से ग्रामीण समाज में जागरूकता बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी मजबूत हुई है और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। साथ ही, सामाजिक असमानताओं में आंशिक कमी और सामुदायिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई है। हालांकि, संसाधनों का असमान वितरण, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा पलायन जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि फर्रूखाबाद जनपद की नीतिगत भूमिका ने ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी है, किंतु सतत और संतुलित प्रगति के लिए योजनाओं की पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति-निर्माण को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

1. मिश्रा, आर. (2020). ग्रामीण आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास: एक क्षेत्रीय अध्ययन. *भारतीय ग्रामीण योजना जर्नल*, 18(2), 45–52.
2. तिवारी, एस. (2019). उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. *विकास और प्रशासन*, 13(3), 67–74.
3. वर्मा, के. (2021). ग्रामीण भारत में जल आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति. *जल प्रबंधन पत्रिका*, 9(1), 23–30.
4. पांडे, एन. (2018). ग्रामीण अधोसंरचना में बिजली की भूमिका: विकास की दृष्टि से. *ऊर्जा और नीति अध्ययन*, 5(4), 101–108.
5. यादव, बी. (2020). प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण जीवन स्तर. *ग्रामीण स्वास्थ्य समीक्षा*, 11(2), 84–91.
6. चौधरी, एम. (2017). शिक्षा अधोसंरचना और आर्थिक सशक्तिकरण: एक तुलनात्मक विश्लेषण. *भारतीय शिक्षा नीति जर्नल*, 14(1), 57–63.
7. शुक्ला, ए. (2019). प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ग्रामीण बाजारों पर प्रभाव. *सड़क और अर्थव्यवस्था*, 8(3), 33–41.
8. त्रिपाठी, एल. (2021). ग्रामीण परिवहन व्यवस्था और कृषि विपणन. *कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र*, 10(1), 72–78.
9. गुप्ता, एस. (2020). ग्रामीण इंटरनेट अधोसंरचना का युवाओं पर प्रभाव. *डिजिटल भारत जर्नल*, 3(2), 91–97.

10. राठी, वी. (2018). क्षेत्रीय असमानता और अधोसंरचना विकास में अंतर्विरोध. *विकास विमर्श*, 12(4), 49–56.
11. दीक्षित, आर. (2022). अधोसंरचना निवेश और ग्रामीण रोजगार सृजन. *आर्थिक सुधार और योजना*, 9(3), 101–109.
12. शर्मा, जे. (2019). शिक्षा व स्वास्थ्य अधोसंरचना की भूमिका आर्थिक प्रगति में. *सामाजिक विकास अध्ययन*, 15(2), 66–73.
13. भटनागर, एम. (2021). ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल समावेशन. *संचार नीति शोध पत्रिका*, 4(1), 39–45.
14. सिंह, आर. (2020). ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि अवसंरचना की भूमिका. *कृषि योजना समीक्षा*, 6(2), 88–95.
15. कश्यप, टी. (2019). जल जीवन मिशन और ग्रामीण जल संरचना: एक मूल्यांकन. *जल विज्ञान एवं नीति पत्रिका*, 5(4), 58–65.
16. निगम, डी. (2018). ग्रामीण विकास में पंचायत आधारित अधोसंरचना योजनाएँ. *स्थानीय शासन जर्नल*, 7(3), 27–34.
17. मिश्रा, एस. (2022). उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना विकास की वर्तमान स्थिति. *राज्य स्तरीय नीति विश्लेषण*, 11(1), 93–101.
18. कुशवाहा, एल. (2020). ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग अधोसंरचना और वित्तीय समावेशन. *ग्रामीण वित्त पत्रिका*, 2(2), 55–61.
19. तोमर, ए. (2021). सड़क व सिंचाई अधोसंरचना और कृषि उत्पादन. *सिंचाई प्रबंधन पत्रिका*, 6(3), 74–81.
20. वाजपेयी, पी. (2022). ग्रामीण अधोसंरचना और प्रवासी मजदूरों की वापसी के प्रभाव. *सामाजिकी और विकास*, 10(2), 112–119.